http://krishipravahika.vitalbiotech.org/

कृषि प्रवाहिका: ई-समाचार पत्रिका

e-ISSN: 2583 – 0430

कृषि-प्रवाहिका: ई-समाचार पत्रिका, (2025) वर्ष 5, अंक 7, 19-21

Article ID:447

जनजातीय क्षेत्रों में पोषण, आय और सशक्तिकरण का उपाय: कुक्कुट पालन

प्रसन्न गोडबोले[1] और अंजली आर्या[2]*

[1]पशु चिकित्सा औषधि विज्ञान एवं विषविज्ञान विभाग, एम. बी. वेटरिनरी कॉलेज, (राजुवास) - 314001 (राजस्थान), भारत

[2]पशु उत्पादन प्रबंधन विभाग, एम. बी. वेटरिनरी कॉलेज, (राजुवास) - 314001 (राजस्थान), भारत

भारत के जनजातीय समुदायों की पारंपरिक आजीविका में कुक्कुट पालन (मुर्गी पालन) एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभर रहा है, जो सामाजिक, आर्थिक और पोषणीय दृष्टिकोण से अत्यंत प्रभावशाली है। यह गतिविधि कम लागत, न्यूनतम संसाधनों और सीमित प्रशिक्षण में भी सफलता प्राप्त कर सकती है, विशेषतः महिलाओं और छोटे किसानों के लिए। वर्तमान शोध में यह स्पष्ट किया गया है कि कुक्कुट पालन न केवल आदिवासी परिवारों की आयवृद्धि में सहायक है, बल्कि कुपोषण की समस्या का समाधान भी प्रदान करता है। लेख में कुक्कुट पालन की सामाजिक एवं आर्थिक भूमिका, पोषण सुरक्षा में योगदान, सरकारी योजनाओं की भूमिका, चुनौतियाँ और उनके समाधान तथा विभिन्न राज्यों के सफल उदाहरणों का विश्लेषण किया गया है। विशेषकर महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कुक्कुट पालन ने आदिवासी समाज में आत्मनिर्भरता, निर्णय-निर्माण की क्षमता और आर्थिक सहभागिता को बढ़ाया है। यह अध्ययन सुझाव देता है कि यदि सरकारी एवं गैर-सरकारी सहयोग से प्रशिक्षण, टीकाकरण, बाजार संपर्क और वित्तीय सहायता की व्यवस्थाओं को और सशक्त किया जाए, तो कुक्कुट पालन आदिवासी समाज के समग्र विकास का एक कुंजीभूत माध्यम बन सकता है।

1. परिचय

भारत में जनजातीय समुदाय एक महत्वपूर्ण सामाजिक वर्ग हैं, जिनकी जनसंख्या लगभग 10 करोड़ से अधिक है। ये समुदाय प्राचीन काल से ही प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित जीवन शैली अपनाए हुए हैं। आदिवासी समुदायों की जीविका मुख्यतः कृषि, वनोपज संग्रह, मछली पालन और पशुपालन जैसे परंपरागत साधनों पर निर्भर करती है। इनमें *कुक्कुट पालन* (मुर्गी पालन) एक महत्वपूर्ण और व्यवहारिक साधन है जो कम पूंजी, कम संसाधन और स्थानीय परिस्थितियों में भी सफलता से संचालित किया जा सकता है।

कुक्कुट पालन न केवल आय का स्रोत है, बल्कि पोषण सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और

आत्मनिर्भरता की दिशा में एक प्रभावशाली उपाय है। यह विशेषकर आदिवासी महिलाओं के लिए एक ऐसा साधन है, जिससे वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकती हैं। हाल के वर्षों में सरकार द्वारा ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, जिनसे इन समुदायों को नई दिशा मिली है।

2. कुक्कुट पालन का सामाजिक और आर्थिक महत्व

कुक्कुट पालन आदिवासी समाज में पारंपरिक रूप से प्रचलित एक लघु व्यवसाय है, जो अब आधुनिक तकनीकों और सरकारी सहायता से एक व्यवस्थित आय-स्रोत के रूप में उभर रहा है। आदिवासी परिवार, विशेषकर महिलाएं, देसी नस्ल की मुर्गियाँ पालती हैं जो खुले वातावरण में स्वतः चरती हैं और सीमित देखभाल में भी उत्पादन देती हैं। यह पारंपरिक प्रणाली कम लागत पर चलती है और छोटे पैमाने पर भी स्थायी आय प्रदान करती है।

आर्थिक दृष्टि से कुक्कुट पालन आदिवासी परिवारों को अतिरिक्त आय देता है जिससे वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। कुछ राज्यों में यह व्यवसाय परिवार की मासिक आय में ₹3000–₹8000 तक का योगदान करता है। सामाजिक दृष्टिकोण से यह आदिवासी महिलाओं को निर्णय लेने की शक्ति देता है, जिससे वे आत्मनिर्भर बनती हैं। सामूहिक रूप से किया गया कुक्कुट पालन सामाजिक एकता को भी बढ़ावा देता है, जहाँ महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं, चारा प्रबंधन करती हैं और उत्पादनों की बिक्री करती हैं। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल देता है और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को कम करने में सहायक सिद्ध होता है।

3. पोषण और स्वास्थ्य पर प्रभाव

आदिवासी समुदायों में कुपोषण एक गंभीर सामाजिक-स्वास्थ्य समस्या है। विशेषकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों में प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 आदि की कमी देखी जाती है। ऐसे में कुक्कुट पालन एक व्यावहारिक समाधान प्रदान करता है। अंडा और मुर्गी का मांस उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन स्रोत है, जो न केवल शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। कुक्कुट पालन से घर में नियमित रूप से अंडे और मांस उपलब्ध होने पर परिवार की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इससे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में सुधार देखा गया है। कई सरकारी योजनाएँ जैसे मिड-डे मील और आंगनवाड़ी कार्यक्रमों में अंडे को शामिल करने के पीछे यही उद्देश्य है कि पोषण स्तर सुधारा जा सके।

स्वास्थ्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुक्कुट उत्पादों का सेवन एनीमिया, कमजोरी, और कुपोषण जनित रोगों में कमी लाता है। यदि हर आदिवासी परिवार को 5-10 मुर्गियों का पालन करने के लिए सक्षम बनाया जाए, तो स्थानीय स्तर पर पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। इस दिशा में नीति समर्थन अत्यंत आवश्यक है।

4. सरकारी योजनाएँ और सहयोग तंत्र

कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में आयवृद्धि और पोषण सुधार है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), और ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन (TRIFED) द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में पोल्ट्री यूनिट स्थापना हेतु अनुदान, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। इन योजनाओं के तहत आदिवासी परिवारों को टीकाकरण, चारा प्रबंधन, पोल्ट्री शेड निर्माण और बाज़ार से जोड़ने की प्रक्रिया में सहायता दी जाती है। कई राज्यों ने अपने बजट में विशेष "आदिवासी पशुपालन योजना" भी चलाई है, जिसके अंतर्गत महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को प्राथमिकता दी जाती है।

इसके अतिरिक्त, कई गैर-सरकारी संगठन और CSR परियोजनाएं भी कुक्कुट पालन को आदिवासी सशक्तिकरण का माध्यम बना रही हैं। प्रशिक्षण शिविर, पोल्ट्री फीड वितरण, रोग प्रबंधन, और विपणन से संबंधित मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। इन सब प्रयासों से आदिवासी समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ठोस आधार तैयार हो रहा है।

5. प्रमुख चुनौतियाँ और समाधान

यद्यपि कुक्कुट पालन आदिवासी समुदायों के लिए एक व्यवहारिक विकल्प है, फिर भी इसमें कई चुनौतियाँ हैं जो इसके विस्तार में बाधा बनती हैं। सबसे बड़ी समस्या रोग प्रबंधन की है।

मुर्गियों में न्यूकैसल डिज़ीज़, कोरिज़ा, एवियन इंफ्लूएंजा जैसे रोग फैलने की संभावना अधिक रहती है, जिससे पूरा उत्पादन प्रभावित हो सकता है। दूसरी चुनौती है तकनीकी जानकारी की कमी, जिससे पोल्ट्री का आधुनिक प्रबंधन नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त, बाज़ार तक पहुँच, उचित मूल्य की प्राप्ति, और चारा प्रबंधन भी गंभीर समस्याएं हैं। कई आदिवासी क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवाओं की अनुपलब्धता, टीकाकरण की कमी और प्रशिक्षण केंद्रों की दूरी पालनकर्ताओं को हतोत्साहित करती है।

इन समस्याओं के समाधान हेतु सरकार को चाहिए कि वह गांव स्तर पर पोल्ट्री हेल्थ वर्कर तैयार करे, चलित टीकाकरण सेवाएँ आरंभ करे और डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से उत्पादकों को सीधे ग्राहकों से जोड़े। महिला SHG को उद्यमिता प्रशिक्षण दिया जाए और सामूहिक विपणन की संरचना को मज़बूत किया जाए, जिससे आदिवासी समुदाय न केवल आत्मनिर्भर बनें, बल्कि स्थायी आजीविका प्राप्त कर सकें।

6. केस स्टडी / उदाहरण

देश के कई हिस्सों में आदिवासी महिलाओं और युवाओं द्वारा कुक्कुट पालन के सफल उदाहरण सामने आए हैं, जो इस क्षेत्र की संभावनाओं को दर्शाते हैं। झारखंड के गुमला और खूंटी जिलों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों ने सामूहिक रूप से पोल्ट्री फार्म संचालित कर अपनी मासिक आय ₹6000–₹10000 तक बढ़ाई है। इन्हें राज्य सरकार और NABARD द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। ओडिशा के क्योंझर और मयूरभंज जिलों में 'बैकयार्ड पोल्ट्री मॉडल' को सफलतापूर्वक अपनाया गया है, जहाँ आदिवासी परिवारों को 25-30 मुर्गियों के साथ पोषण किट्स और नियमित टीकाकरण सुविधाएँ उपलब्ध कराई गईं। इसका सकारात्मक प्रभाव बच्चों के पोषण स्तर पर भी देखा गया।

छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में कुक्कुट पालन को युवाओं के लिए स्वरोजगार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ प्रशिक्षण केंद्रों की मदद से स्थानीय नस्लों के साथ-साथ उन्नत नस्लों का पालन किया जा रहा है। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़े हैं, बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक विकास में भी योगदान हुआ है।

7. निष्कर्ष और सुझाव

कुल मिलाकर, कुक्कुट पालन आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक उन्नति का सशक्त माध्यम बन सकता है। यह व्यवसाय कम लागत में प्रारंभ होने के कारण छोटे किसानों और महिलाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। इससे पोषण सुरक्षा, आयवृद्धि और आत्मनिर्भरता तीनों लक्ष्यों की पूर्ति संभव है। सरकार, गैर-सरकारी संगठनों और शोध संस्थानों को मिलकर एक एकीकृत रणनीति बनानी चाहिए, जिसमें प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, पशु स्वास्थ्य सेवाएं, विपणन और नीति समर्थन शामिल हों। *"एक परिवार – दस मुर्गियाँ"* जैसी योजनाएँ स्थानीय स्तर पर लागू कर दी जाएँ, तो इसका प्रभाव देशव्यापी हो सकता है। इस प्रकार, कुक्कुट पालन न केवल एक आर्थिक गतिविधि है, बल्कि यह आदिवासी समाज के सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सुधार और समावेशी विकास की दिशा में एक दृढ़ कदम है।